आवास के दूरभाष / मोबाइल खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु उन्हें मु0 3800 / – fixed राशि द्विमासिक देय होगी।

6. (क) बोर्ड के सलाहकार उसी निशुल्क चिकित्सा सुविधा के पात्र होंगे जिसके लिए बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक पात्र है।

(ख) सलाहकार यात्रा दैनिक भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए सक्षम होंगे तथा प्रवास कार्यक्रम को अनुमोदन करने के लिए स्वयं ही नियन्त्रण अधिकारी होंगे।

(ग) इनके बिलों का आहरण बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

7. सलाहकार को मु0 30000 / – रु0 प्रतिमास के दर से पारिश्रमिक देय होगा।

8. सलाहकार को पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में पूर्व की भान्ति मु0 8.00 (आठ रुपये) प्रति कि0 मी0 की दर से मील भत्ता (रोड माईलेज) देय होगा, यदि वे निजी वाहन द्वारा बोर्ड के कार्य से प्रवास पर जाते हैं।

उपरोक्त सभी सुविधायें एवं सेवा शर्तें वित्त विभाग के दैनिकी संख्या 55048086–वित्त (सी)बी(15)–4 / 2016, दिनांक 26–6–2020 द्वारा जारी संस्तुति व विधि विभाग द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष के 30% वेतन आदि को कम करने की शर्त के अधीन जारी की जाती है।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (कृषि)।

————————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 जुलाई, 2020

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–8 / 2020–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06–07–2020 को अनुमोदित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम**.––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 है।

2. **धारा 1 का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) की धारा 1 की उपधारा (4) में शब्द ''बीस'' जहाँ–जहाँ आता है के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

हस्ता0 / –
(बंडारू दत्तात्रेय),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता0 / –
(यशवन्त सिंह चोगल),
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 2020

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ORDINANCE, 2020

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE, to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020.

2. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970), in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub- section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.

Sd/-
(BANDARU DATTATREYA)
Governor,
Himachal Pradesh.

Sd/-
(YASHWANT SINGH CHOGAL),
Principal Secretary (Law).

Shimla:

Dated …….. 2020

———————

मैं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हं।

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

———————

माननीय राज्यपाल ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

यशवन्त सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।